IAS Mentorship

With Reyasat Ali sir & Experienced team in CSE prep

CSE Main 2023: Mini Mock Test 6

Syllabus:	• • Governance & Social Justice • •
Name of Candidate	MOHAN MANGAWA
Email Id	
Date	Medium: Hindi / English
Time: 1 Hour	Start Time: / End Time:

Q. No.	Max. Marks	Marks obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	15	
5	15	
6	15	
7	15	
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
Total	90	
Invigilator	Signature	

total 32

WhatsApp/Telegram/Text/Call: 8090528260

Scanned with OKEN Scanner

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

	Excellent	Good	Average	Unsatisfied
Introduction				
Conceptual Understanding				
Contextual Clarity				
Content Enrichment				
Presentation				
Alignment				
Contextual Justification				

Dear aspirant

your this attempt is average as compared to the previous one

I think you have not understood the demand of the question in civil servants questions

also there was less emphaisis on explaining thing and more on providing data see raw data is also not desirable you need to provide a mix of both concept as well as data

structure is always good and to the point

presentation has scope of improvement you can always draw more diagram as done in pds question that will give brownie point

all the best and keep writing

Scanned with OKEN Scanner

Q1. "It is necessary to reorient policy discourse to reflect social reality to lay foundation for a new social justice program". In the context of above statement analyze the pros and cons associated with caste census in Indian. 150 words

जॉन रॉल्स के अनुसार सामाजिक न्याय एक निरंतर परिवर्तित होती प्रक्रिया है जो समय के साथ विभिन्न अवधारणाओं को समाहित करने पर जोर देती है।

जाति विविधता व जातियों में बढ़ी हुआ सामाजिक-आर्थिक असमानता के कारण आजकल जाति आधारित जनगणना की मांग बढ़ी है जिसके सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभाव है

सकारात्मक → जातिय पहचान → पॉलिसी निर्माण को आसान बनायेगी

↳ आरक्षण का तार्किकीकरण ⇒ इन्क्लूजन एक्सक्लूजन एरर कम होंगे

↳ पिछड़े क्षेत्रों तक लोककल्याण संभव
↳ योजनाओं का लाभ
↳ स्पष्ट पहचान संभव

your intro is good but you are advised not to use optional thinkers in your answer gives a bad impression

mention castesim morphology getting changes and getting new dimensions

also caste is generally relates to state of poverty and policy formulation can benefit these

Scanned with OKEN Scanner

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

↳ सरकार को स्पष्ट डेटा की प्राप्ति

↳ OBC के संबंध में अपर्याप्त डेटा

नकारात्मक → जातीय भावना को प्रबलता → जातिवाद व समाज विघटन खतरा

↳ दलित जातियों के साथ शोषण होने की संभावना → जातिय प्रबलता व अधिकार प्राप्ति इच्छा के कारण

↳ OBC वर्गों में आरक्षण की मांग तीव्र होगी → जनसंख्या : आरक्षण अनुपात में बड़ा अन्तर के कारण

↳ जाति आधारित राजनीतिक ध्रुवीकरण

जरूरत → जाति आधारित जनगणना करते हर सरकार द्वारा निष्पक्ष जाँच

↳ पिछड़े जातीय समूहों हेतु आरक्षण व उप-वर्गीकरण जैसी व्यवस्था

↳ क्षेत्र आधारित कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण।

का हुड़ सत्य है कि इस प्रकार जाति भारतीय समाज का अभिन्न अंग है। अतः इस संबंध में पिछड़े जातीय समूहों को बाहर करने में जातिगत गणना उपयोगी साबित होगी।

caste still plays a major role in election and it can result in criminalisation of election

you have mentioned good points

you can always conclude the need of caste census in your answer

4/10

Scanned with OKEN Scanner

Q2. Examine the potential benefits of Digitalization of Land records in India. 150 words

भूमि के डिजिटलीकरण का अर्थ है - भूमि रिकॉर्ड, मालिकों, सीमा व इसके आकार का सम्पूर्ण डाटा डिजिटल रूप से उपलब्ध होना। इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं।

start with various initiatives taken by state government for digitalisation of land records

भू-डिजिटलीकरण की जरूरत

- भू-सुधार का प्रमुख अंग
  - सरकार के पास सटीक डाटा उपलब्धता
- गैर-कानूनी भूमि हस्तांतरण पर रोक
  - मुख्यतः SC-ST वर्ग के बीच
- स्थानीय बिचौलियों व जमींदारी वर्ग के प्रभुत्व कम करने में सहायता
- 85% सीमांत किसान → अतः FPO व FPCs बनाकर चकबंदी प्रक्रिया को तीव्र करना

also cases will be reduced in already over burdened judiciary

you can always include bhoodan andolan of vinoba bhave in kand reforms and zamindari eradication

Scanned with OKEN Scanner

↳ सरकारी योजनाओं का तार्किकरण
  ↳ KCC व उर्वरक सब्सिडी को भू-अभिलेख से जोड़कर बेहतर किसान-सहायता

issue of tribals lands not having proper titles and land passing through generations

परन्तु समस्याएं → स्थानीय स्तर पर प्रमाणित डेटा की कमी → पटवारी, तहसीलदार के पास पुराना डेटा

↳ डिजिटल डिवाइड → केवल 37% डिजिटल साक्षरता (इंडिया इंटरनेट रिपोर्ट 2021)

↳ जागरूकता अभाव व छोटी जोत के कारण उत्साह कम

issue of data theft also

↳ डिजिटलीकरण कार्यक्रमों का स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन मुश्किल → भौगोलिक
→ प्रशासनिक बाधाएं

जरूरत → स्थानीय स्वशासित निकायों को पटवारी-ग्राम सेवक के साथ मिलकर डाटा-अद्यतन कार्य

↳ 'भूमि' (KA) व SVAMITVA जैसी योजनाओं के प्रति जागरूकता

good 5/10

↳ KCC व अन्य सब्सिडी प्लेटफार्म पर डिजिटल डाटा अनिवार्य करना → केरल एक स्टेक सिद्धान्त

इस प्रकार एक बेहतर डाटा उपलब्धता देश की बड़ी जनसंख्या को बेहतर अवसर प्रदान करेगा साथ ही सरकार के भी राजकोष पर कम दबाव पड़ेगा।

Scanned with OKEN Scanner

Q3. "Human life, above all". In this context critically examine the pros and cons associated with Right to Health act passed in Rajasthan. Do you think this is a step towards achieving Health as a fundamental right at national level? 150 words

जीवन का अधिकार अनु॰ 21 के अनुसार मूलभूत व प्राकृतिक अधिकार है जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा मानेका गांधी वाद (1978) में और अधिक विस्तृता प्रदान की गई।

इसी को आधार बनाकर राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में स्वास्थ्य अधिकार का सार्वभौमिकरण किया गया जो एक

सराहनीय कदम है–

- पिछड़े व गरीब जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा
- अच्छे अस्पतालों व आधुनिक स्वास्थ्य लाभों तक आम आदमी की पहुँच संभव
- #SDG लक्ष्यों 1, 2, 3 की प्राप्ति हेतु आवश्यक
- बेहतर स्वास्थ्य जनसांख्यिकीय लाभांश में सहयोग होगा ⇒ आर्थिक लाभ

intro is good but you can also start with data of less percentage of GDP spends on health

also will counter high out of pocket expenditure

Scanned with OKEN Scanner

परन्तु यह कदम कुछ समस्याओं का सामना कर सकता है-

① निजी स्वास्थ्य क्षेत्र का विरोध
→ गुणवत्तापूर्ण सेवा हेतु प्रोत्साहन खत्म

② सरकार के राजकोषीय व्यय पर अधिक भार ⇒ घटती राजकोषीय प्रगति ⇒ अर्पित सकर

③ आधारभूत स्वास्थ्य संरचनाओं की अभी भी पिछड़े क्षेत्रों में पहुँच नहीं।

④ सरकारी अस्पतालों की प्रासंगिकता कम होगी ⇒ अतिरिक्त व्यय भार।

हाँ० राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य को मूलाधिकार घोषित किया जा सकता है लेकिन राजकोषीय घाटे व उपरोक्त समस्याओं का उचित समाधान पूर्वशर्त है। इसके लिए राज्य व केन्द्र दोनों को सभी हितधारकों (जनता, निजी अस्पताल, सिविल सोसायटी, विशेषज्ञ) के साथ एक बेहतर रणनीति बनानी होगी।

issue of also high fiscal deficit

facilities issue

mention spending GDP on health and universalisation of primary health care as a viable option

3/10

Scanned with OKEN Scanner

Q4. The PDS is the biggest food network program in the world yet India witnesses' food insecurity, malnutrition and hunger challenges. Discuss reasons, also Explain the reasons along with suitable suggestions. 250 words

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधि. 2013 के तहत 67% जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति हेतु PDS प्रणाली को अपनाया गया जो 'उचित मूल्य की दुकानों' के माध्यम से चावल / गेहूँ / दाल आदि का क्रमशः 3/2/1 रु/kg पर गरीब जनता को वितरण करती है।

thats the provision of national food security act. pds was before that only

PDS खाद्य नेटवर्क विकास

1992 — IPDS (लक्षित)
1996 — TPDS (संशोधित)
2000 — अंत्योदय अन्न
→ सार्वभौमिकरण NFSA

very good representation

परन्तु आने वाली समस्याएं

① FPS की ओर से /
- → अपर्याप्त अवसंरचना
- → डिजिटलीकरण का अभाव
- → FPS दुकानदारों द्वारा कालाबाजारी & मिलावट
- → बिचौलियों के साथ सम्बन्ध
- → समय पर नहीं खुलना

hoarding by the shopkeepers

Scanned with OKEN Scanner

② FCI की ओर से → अनाजों का सामता से तीन गुना संग्रहण
↳ खाद्य वितरण में अपारदर्शिता → गुणवत्ता में कमी
सड़ा-गला अनाज
↳ ट्रकों पर निगरानी अभाव → अनाज विक्षेप
↳ FCI को फंडिंग की कमी → Extraa Budgetery Resources का सहारा

③ संस्थागत भ्रष्टाचार
↳ घोस्ट कार्डधारकों की बड़ी संख्या
↳ समावेशन - एक्सक्लूजन त्रुटि
2011 जनगणना आधारित (प्रयत्न)
↳ खाद्य कीमतों का मुद्रास्फीति के साथ जुड़ाव नहीं → बाजार में महंगाई

अत: उपरोक्त समस्याओं को दूर करने हेतु कुछ निम्न कदम उठाने की जरूरत है—
⇒ डिजिटलीकरण का सहारा → FPS को e-POS से जोड़ना
↳ FCI स्टॉकों की जियो टैगिंग
↳ आधार-मोबाइल लिंक

rotting of food grains no proper storage

good points mentioned by you

Scanned with OKEN Scanner

⇒ डेटा अद्यतनीकरण → रजिस्ट्रार जनरल के नियमित डेटा का प्रयोग
↳ आधार - JAM का प्रयोग

issue if aadhar card leakages

also duplication

⇒ लिकेज पर रोक → FCI गोदामों का PPP मॉडल → स्थानीय क्षेत्रों में स्थापित करना
↳ सबसे गरीब 21% (तेंदुलकर समिति) को ही 3/2/1 रु/Kg पर उपलब्धता
अन्य को (APL) थोड़ा अधिक कीमत पर अनाज।

⇒ शांता कुमार समिति सिफारिशें लागू करना
↳ FPS को स्थानीय स्वशासन निकायों से प्रबंधन
↳ MSP का तार्किकीकरण ⇒ FCI पर दबाव कम हो
↳ प्राइस डेफिसिएंसी मार्केट जैसे तंत्रों का प्रयोग
↳ FCI गोदामों की अवस्था को सुधारना
↳ बेहतर प्रिजर्वेशन व सुरक्षा
लोगों से दूर अवस्थिति।

इस प्रकार एक बेहतर लॉजिस्टिक्स सिस्टम व वितरण प्रणाली द्वारा ही SDG लक्ष्यों 1, 2, 2.4 की प्राप्ति संभव होगी।

you can always mention about what can be done to improve the pds system in a nutshell welcome jam Trinity as a good step

5/15

Scanned with OKEN Scanner

Q5. In the context of "Sangathan se Samridhhi- Leaving no Rural Women Behind", discuss the potential of Self-Help Group (SHG) Movement in the women empowerment and poverty alleviation in present time.
250 words

समान पृष्ठभूमि व हितों वाले व्यक्तियों द्वारा स्वयं आकर आर्थिक व्यावसायिक समूह का निर्माण करना SHG का उदाहरण है। जैसे - लिज्जत पापड़ । MAVIM आदि।

ES - 2020-21 के अनुसार देश के 90% SHGs में महिलाओं द्वारा संचालित है। जो करोड़ों गरीब महिलाओं के जीवन का आधार बना है।

SHGs द्वारा महिला सशक्तिकरण

1. गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता तंगी
2. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा उदा० कुटुम्बश्री SHGs
3. महिलाओं में उद्यमिता व आर्थिक कार्यप्रणाली से जुड़ाव

good introduction good examples given

more gender parity

Scanned with OKEN Scanner

④ महिला आर्थिक व्यवस्था का औपचारिकरण
[NABARD के अनुसार 87% SHGs द्वारा बैंकों से ऋण प्राप्ति]

⑤ सामाजिक सशक्तिकरण
↳ पितृसत्तात्मक सोच पर प्रहार
उदा. मिरलेवहम (KL) SHG द्वारा महिला सदस्यों को लिंग-समानता पर बल।
↳ पारिवारिक व्यवस्था में उचित स्थान प्राप्ति ⇒ सम्मान, बेहतर जीवन स्तर
↳ शिक्षा - स्वास्थ्य स्तर में बेहतरी

⑥ SDGs लक्ष्यपूर्ति / → गरीबी, कुपोषण व महिला समानता की ओर।

very good points mentioned by you

परन्तु इसमें अभी भी कई समस्याएं हैं

⇒ अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा → वित्तीय समावेशन & साक्षरता अभाव
⇒ महिलाओं में जागरूकता अभाव → निरक्षरता अधिक
↳ ग्रामीण क्षेत्रों की दुर्गमता

Scanned with OKEN Scanner

⇒ SHGs आंदोलन में असमानता
↳ बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान व पूर्वी - पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कमी

⇒ महिलाओं की खराब सामाजिक स्थिति
↳ केवल ~2% महिलाओं के संपत्ति नामकरण (RBI रिपोर्ट)
↳ ~53% महिलाएं कुपोषित (NHFS-V)

अतः जरूरत → SHGs को माइक्रो-फाइनेंसिंग से जोड़ना (SHG-बैंक लिंक स्कीम)
↳ बुनियादी अवसंरचना - डिजिटलीकरण व पंचायत स्तरों के माध्यम से जागरूकता
↳ आर्थिक पैकेज → प्रदर्शन आधार पर (जिवनकी स्कीम (GJ))
↳ बैंकों द्वारा दिए गए SHGs ऋण की समय पर ऑडिटिंग व टर्म शीट निगरानी

इस प्रकार बेहतर जागरूकता व पहले से उपस्थित SHGs द्वारा यदि सरकार - वित्तीय संस्थानों के साथ प्रयास किए जाएंगे तो SHGs 13 करोड़ महिलाओं से 30 करोड़ महिलाओं के सहायता करने में सहायक होंगे।

good use of the data

very good answer good presentation 7/15

Scanned with OKEN Scanner

Q6. Indian is speeding towards integrating technology in Governance and goods and service delivery both. All this requires a worker (Civil Servant) who is not just committed but also has the competence to deliver on this evolving mandate. Comment 250 words

UNESCAP के अनुसार राज्य द्वारा बेहतर व समयबद्ध सेवाओं की प्रदायगी हेतु एक अच्छे शासन (सुशासन) ढाँचे की जरूरत होती है जो नवाचार व नवीन तकनीकी पर कार्य करता है।

intro can be improved you can mention civil servants as agents of change in a society

भारत द्वारा सुशासन हेतु प्रयास

↳ नागरिक चार्टर की अनिवार्यता

↳ लोकपाल - लोकायुक्त अधिनियम 2013

↳ CVC, CBI आदि द्वारा सिविल सेवकों के कार्यों की वैधता जाँच

good

↳ सेवोत्तम मॉडल

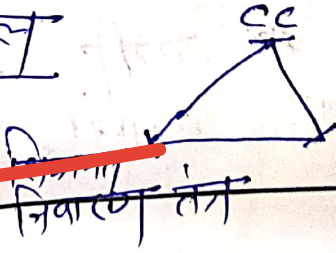

link with the challanges brought down by digitalisation

Scanned with OKEN Scanner

↳ व्हिसल ब्लोअर एक्ट 2014 व RTI Act 2005 का पालन अनिवार्य

↳ ई-गवर्नेंस व ICT का बढ़ता प्रशासनिक संस्थागत प्रयोग → भ्रष्टाचार को रोकने में कारगर।

परन्तु इसमें भी समस्याएं भी हैं

सिविल सेवकों की ओर से
↳ यथास्थितिवादी नजरिया → नवाचार नहीं
↳ सेवाओं के प्रति पूर्वाग्रह व गोपनीयता का भाव
↳ बढ़ता भ्रष्टाचारी रवैया (उदा. पूजा सिंघल भ्रष्टाचार केस)
↳ भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अभाव के कारण करुणा, सहानुभूति जैसे मूल्यों की कमी → कार्यबोझ प्रबंधन क्षमता कमजोर।

mention it in respect to the changes in governance mention about citizenship model

issue of postings and transfers

Scanned with OKEN Scanner

बुनियादी समस्याएं।

↳ बदला ट्रिपल डिवाइड (ग्रामीण-शहर, महिला-पुरुष, डिजिटल)

↳ राजनीति का अपराधीकरण → सहानुभूति व सामाजिक अनुबंधों का टूटना

↳ भौगोलिक प्रसार के कारण गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध सेवापूर्ति कठिन

↳ केन्द्र-राज्य संबंधों की कमजोरी।

↳ विवादों ने गवर्नेंस को कमजोर किया।

जरूरत → सिविल सेवकों के उचित प्रशिक्षण व समता निर्माण जरूरत → मिशन कर्मयोगी जैसे कार्यक्रम

↳ सेवाओं का स्थानीयकरण ⇒ सिविल सेवकों द्वारा जनता से संवाद ⇒ समस्या हल प्रभावी

↳ लेटरल एंट्री व मोड ऑफ कंडक्ट की कानूनी अनिवार्यता लागू करना जरूरी।

इस प्रकार एक बेहतर प्रशासन संचालन हेतु सिविल सेवक सबसे सेतु हैं जो सेवाओं को बेहतर बनाकर सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक न्याय के गांधीजी के सपने को साकार कर सकते हैं।

the question is about civil servants and how they need to adopt to changes dynamics

you have digressed from the topic

good suggestion also you can mention about domain expertise that can be brought

3/15

Scanned with OKEN Scanner

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

Q7. Same sex (Homosexual) Community has been one of the most marginalizes communities in Inda. Do you agree that the recognition of same sex marriage will help them to improve their situation. Give your argument in favor your opinion. 250words

NCRB डेटा के अनुसार LGBTQ+ समूह के खिलाफ 2018–2021 के बीच अपराधों में ~68% की वृद्धि हुई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 377 हटाने के लक्ष्यों / उद्देश्यों की प्राप्ति में एक बड़ी बाधा परिलक्षित हो रही है।

very good intro good use of the data

LGBTQ+ के साथ समस्याएं

- सामाजिक कलंक के रूप में पहचान
- सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं किया जाना
- आर्थिक क्षेत्रों, रोजगार आदि में अयोग्य समझना
  - भीख मांगने को मजबूर
- समलैंगिकता के कारण आने वाली स्वास्थ्य समस्याएं

issue of employment not given and most important is social ostrasization that needs to be included

समलैंगिक विवाह – क्या सही में लाभदायक

पक्ष → सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 377 हटाकर वैध किया जाना

↳ व्यक्तिगत स्वतंत्रता व जीवन (गरिमापूर्ण) जीने का अधिकार (अनु॰ 21)

↳ दो व्यक्तियों का निजी फैसला

↳ स्वास्थ्य लाभ → मनोवैज्ञानिक संबल
एक दूसरे का साथ →
बेहतर आर्थिक साधन व जीवन स्तर।

↳ समाज की विचारधारा में बदलाव लाने हेतु शुरुआती कदम जरूरी

विपक्ष → सरकार द्वारा विरोध
↳ पारिवारिक ढांचे को तोड़ने वाला कदम ⇒ भारतीय समाज में विवाह एक अनुबंध से ज्यादा सामाजिक मसला

↳ समलैंगिक सेक्सुअल संबंध स्वास्थ्य रूप में हानिकारक ⇒ HIV/AIDS व संक्रामक रोग संभव

↳ अप्राकृतिक संबंधों को मंजूरी देने वाला अर्थ

right to privacy fundamental right in puttuswamy

criticise guvenembt stand against human dignity

good against ipc

Scanned with OKEN Scanner

अतः उपरोक्त वाद-विवाद के हल हेतु एक व्यापक व तार्किक विश्लेषण की जरूरत है -

judiciary needs to be step in

① सरकार व अन्य हितधारकों के बीच वार्ता जरूरी

② सभी आशंकाओं जैसे (पारिवारिक ढाँचा संकट, स्वास्थ्य हानि) आदि पर डिस्कस जरूरी है।

③ विशेषज्ञों व सामाजिक धार्मिक - LGBTQ+ संबंधी लोगों के बीच आम सहमति निकालना।

समग्रतः समलैंगिक विवाह अन्य देशों के परिणामों के अनुसार तो अनुसमर्थित होना चाहिए परन्तु भारतीय समाज के अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन करके इसे लागू / मंजूरी देने की आवश्यकता है।

Scanned with OKEN Scanner